

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विभागों की मैराथन समीक्षा

योजनाओं का स्थल निरीक्षण | दाखिल-खारिज की समर्था कराया जाये : मुख्यमंत्री

का हो निदान : हेमंत सोरेन

ग्रामीण विकास विभाग

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इसके तहत मनरेगा, मनरेगा के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया बिसरा हरित ग्राम योजना, बीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और बाबा साहब धीमपाल अंबेडकर आवास योजनाओं के प्राप्ति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कग वारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है। ऐसे में किसानों-मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किये जायें और योजनाओं का क्रियान्वयन बढ़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जिया मैपिंग भी करायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का आवश्यक निर्देश दिये।



विभाग की प्रगति रिपोर्ट

- बिसरा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख डिमारती पौधे लगाये जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है। इसमें 81 फीसदी आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- मनरेगा की लगभग आवास का कार्य लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 75 हजार नवे आवास स्थीकृत किये गये हैं।
- बाबा साहब धीमपाल अंबेडकर आवास योजना के तहत इस वर्ष 11 हजार 155 आवास बनाने का लक्ष्य है। इसमें 62100 आवास स्थीकृत किये गये हैं।
- ग्रामीण योजना के तहत 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव उपलब्ध कराया जाएगा।

किसानों का निबंधन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलायें: सीएम

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश:

- किसान सुख निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलायें।
- इस वर्ष अक्टूबर तक एक हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले ग्रामीण वितरण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव उपलब्ध कराया जाएगा।

ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर

एक पेड़ लगायें, 5 यूनिट बिजली निःशुल्क पायें का करें प्रचार: हेमंत

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निःशुल्क का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा की दिशा में उत्तराधिकारी लगाये गये कदम की जानकारी ली। उन्होंने सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

इसके पर विभाग ने कम आवश्यक निर्देश दिया।

ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर

ऊर्जा विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश:

- राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है।
- बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा संख्या में स्टार्टिपेट अफसर रखें और ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर नियादान करें।

प्रायः विभागीय मजदूरों के लिए ज्यादा

राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री ने राज्यव, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की दाखिल खारिज उत्तराधिकारी नामांतरण, राजस्व संग्रहण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिये। विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में दाखिल खारिज के कुल 12 लाख 97 हजार 967 राज्यव संग्रहण दिया गया। इसमें 5 लाख 84 हजार आवेदनों का नियादान कर दिया गया। जबकि 6 लाख 42 हजार आवेदन रिजेक्ट किये गये। वर्तमान में 528 ऐसे आवेदन में 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दाखिल खारिज के मामलों का यथार्थीष्ठ नियादान करें।

प्रायः विभागीय मजदूरों के लिए ज्यादा

उपायुक्त के लिए गया। इसमें 5 माहों की सुनिश्चित करें।

प्रायः विभागीय मजदूरों के लिए गया।

उपायुक्त क

